RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 331
दि. 04.04.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

महंगाई की रफ्तार के साथ तेज हुआ सफर का खर्च, यूपी के एक्सप्रेसवे पर बढ़ा टोल और आमजन पर बढ़ा बोझ

उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार और आधुनिक सड़क नेटवर्क का प्रतीक बन चुके एक्सप्रेसवे अब आम लोगों की जेब पर थोड़ा और भारी पड़ने लगे हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही राज्य के चार प्रमुख एक्सप्रेसवे—आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड और गोरखपुर लिंक—पर टोल दरों में बढ़ोतरी लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा लिया गया यह निर्णय 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों, व्यापारियों और परिवहन से जुड़े लोगों की लागत में वृद्धि तय मानी जा रही है। हालांकि यह वृद्धि औसतन लगभग दो प्रतिशत बताई जा रही है, लेकिन जब इसे नियमित यात्रा और बड़े पैमाने पर माल परिवहन के संदर्भ में देखा जाए तो इसका असर कहीं अधिक व्यापक और गहरा दिखाई देता है।

राज्य सरकार और यूपीडा का तर्क है कि यह बढ़ोतरी आवश्यक थी क्योंकि बीते कुछ समय में एक्सप्रेसवे के रखरखाव, संचालन और सुरक्षा व्यवस्था की लागत में लगातार इजाफा हुआ है। बेहतर सड़क गुणवत्ता बनाए रखने, हाईटेक निगरानी सिस्टम, पेट्रोलिंग, इमरजेंसी सेवाओं और टोल संचालन में लगने वाले खर्च को संतुलित करने के लिए टोल दरों में संशोधन करना जरूरी हो गया था। लेकिन दूसरी ओर, आम वाहन चालकों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह राहत की खबर नहीं है, क्योंकि पहले से ही बढ़ती महंगाई के बीच यह अतिरिक्त खर्च उनके बजट को प्रभावित करेगा।

नई टोल दरों के अनुसार, दो और तीन पहिया वाहन तथा ट्रैक्टर चालकों को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पूरे मार्ग के लिए 335 रुपये, पूर्वांचल पर 350 रुपये, बुन्देलखण्ड पर 315 रुपये और गोरखपुर लिंक पर 145 रुपये चुकाने होंगे। इसी तरह कार, जीप और वैन जैसे निजी वाहनों के लिए यह शुल्क क्रमशः 675, 700, 635 और 295 रुपये तय किया गया है। हल्के व्यावसायिक वाहन और मिनी बसों के लिए यह दर और अधिक बढ़कर 1065 से 1105 रुपये के बीच पहुंच गई है। बस और ट्रक जैसे भारी वाहनों के लिए तो यह लागत और भी ज्यादा है, जहां आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2150 रुपये और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2240 रुपये तक का टोल देना होगा। भारी मशीनरी और मल्टी-एक्सल वाहनों के लिए यह दर 3000 रुपये से भी ऊपर चली गई है, जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है।

इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रोजाना इन एक्सप्रेसवे का उपयोग करते हैं, जैसे ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, छोटे व्यापारी, टैक्सी और बस ऑपरेटर। हालांकि प्रतिशत के हिसाब से यह बढ़ोतरी मामूली लग सकती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति हर दिन या हर सप्ताह इन मार्गों पर यात्रा करता है, तो यह अतिरिक्त खर्च महीने के अंत में एक बड़ी राशि का रूप ले लेता है। खासतौर पर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां हर छोटी लागत भी अंतिम उत्पाद की कीमत को प्रभावित करती है।

यूपी के ये एक्सप्रेसवे राज्य के विकास की रीढ़ माने जाते हैं। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे जहां पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को गति देता है, वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को राजधानी लखनऊ से जोड़ते हुए आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देता है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जबकि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करता है। ऐसे में इन सड़कों का सुचारू संचालन और रखरखाव भी उतना ही जरूरी है, जितना कि इनकी पहुंच आम जनता के लिए किफायती बनाए रखना।

विशेषज्ञों का मानना है कि टोल दरों में यह बढ़ोतरी एक संतुलन बनाने की कोशिश है, जहां एक ओर सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव के लिए पर्याप्त संसाधन चाहिए, वहीं दूसरी ओर जनता पर अधिक आर्थिक दबाव भी नहीं डालना चाहिए। हालांकि, मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में जब ईंधन की कीमतें, वाहन रखरखाव और अन्य खर्च पहले से ही बढ़े हुए हैं, तब यह टोल वृद्धि लोगों के लिए एक अतिरिक्त चुनौती बनकर सामने आई है।

व्यावसायिक परिवहन क्षेत्र में इसका प्रभाव और भी व्यापक हो सकता है। ट्रक ऑपरेटरों और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को अब अपने किराए और शुल्क में बदलाव करना पड़ सकता है, जिससे वस्तुओं की कीमतों में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि हो सकती है। यानी यह सिर्फ सड़क पर चलने वालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बाजार में मिलने वाली रोजमर्रा की चीजों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि इस फैसले को लेकर व्यापारिक संगठनों और परिवहन यूनियनों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है।

हालांकि सरकार का यह भी कहना है कि एक्सप्रेसवे पर मिलने वाली सुविधाएं—जैसे बेहतर सड़क गुणवत्ता, तेज यात्रा, कम समय में दूरी तय करने की क्षमता और सुरक्षा व्यवस्था—इन टोल दरों को उचित ठहराती हैं। अगर इन सड़कों की तुलना सामान्य हाईवे से की जाए तो एक्सप्रेसवे पर यात्रा अधिक सुगम और समय की बचत करने वाली होती है, जिससे ईंधन की खपत भी कम हो सकती है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ हद तक यह बढ़ा हुआ टोल संतुलित भी माना जा सकता है।

फिर भी, आम लोगों की चिंता अपनी जगह सही है। बढ़ती महंगाई के दौर में हर अतिरिक्त खर्च उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि सरकार भविष्य में टोल दरों के निर्धारण में जनता की क्रय शक्ति, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रभावों को भी ध्यान में रखे। साथ ही, यदि संभव हो तो नियमित उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ रियायतें या पास जैसी सुविधाएं भी दी जा सकती हैं, जिससे उन पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ थोड़ा कम हो सके।

कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में हुई यह बढ़ोतरी एक ऐसा कदम है जो विकास और आर्थिक दबाव के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता नजर आता है। जहां एक ओर यह राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाए रखने में सहायक है, वहीं दूसरी ओर यह आम जनता के लिए एक नई चुनौती भी लेकर आया है। आने वाले समय में इसका वास्तविक प्रभाव किस तरह सामने आता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आर्थिक गतिविधियां, महंगाई और सरकारी नीतियां किस दिशा में आगे बढ़ती हैं।

चार गोलियां, आधा घंटा और जिंदगी की जंग—गाजियाबाद में खून से लथपथ हालत में खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचा हिस्ट्रीशीटर

गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में गुरुवार देर रात हुई एक सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया, जहां एक हिस्ट्रीशीटर युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, लेकिन गोलियां लगने के बावजूद उसने हार नहीं मानी और खुद ही कार चलाकर अस्पताल पहुंच गया। यह घटना न केवल अपराध जगत की भयावह सच्चाई को उजागर करती है, बल्कि उस युवक की जीवटता और जिंदा रहने की जिद को भी सामने लाती है, जिसने चार गोलियां लगने के बावजूद लगभग तीस मिनट तक गाड़ी चलाकर अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश की।

घटना मोदीनगर थाना क्षेत्र के सीकरी कला गांव स्थित एक ढाबे के बाहर की है, जहां राहुल उर्फ कालू नाम का युवक किसी से मिलने के लिए रुका हुआ था। देर रात का समय था और माहौल सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक वहां मौजूद एक युवक के साथ बातचीत के दौरान हालात बदल गए। देखते ही देखते बहस ने हिंसक रूप ले लिया और हमलावर ने बिना किसी चेतावनी के ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। बताया जा रहा है कि राहुल को चार गोलियां लगीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोग इस अचानक हुई फायरिंग से घबरा गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

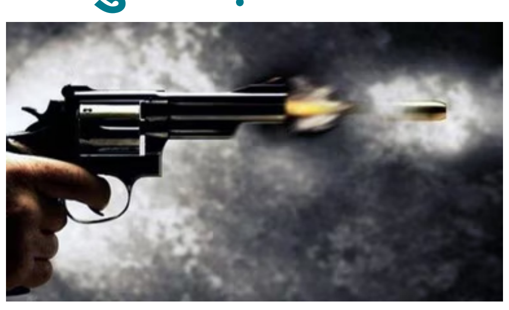

लेकिन इस पूरी घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि इतनी गंभीर हालत में भी राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। खून से लथपथ हालत में, दर्द से कराहते हुए उसने खुद अपनी कार संभाली और अस्पताल की ओर निकल पड़ा। करीब आधे घंटे तक उसने गाड़ी चलाई और आखिरकार अस्पताल पहुंच गया। यह किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था, जहां मौत से जूझता हुआ एक इंसान अपनी आखिरी ताकत जुटाकर जिंदगी की ओर बढ़ता है। अस्पताल पहुंचते ही उसे तुरंत इमरजेंसी में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है और उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

राहुल उर्फ कालू कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह मोदीनगर क्षेत्र का एक जाना-पहचाना हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें रंगदारी, मारपीट और आपसी रंजिश के मामले शामिल हैं। वह पहले भी कई बार जेल जा चुका है और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद वह फिर से इलाके में सक्रिय हो गया था, जिससे उसके पुराने दुश्मनों और विवादों के फिर से उभरने की आशंका बनी हुई थी।

पुलिस की शुरुआती जांच में यह मामला आपसी रंजिश और पुराने विवादों से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। जिस तरह से हमलावर ने सीधे आकर फायरिंग की, उससे साफ है कि यह हमला पूर्व नियोजित हो सकता है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हमलावर राहुल को पहले से जानता था या नहीं, और क्या यह मुलाकात किसी साजिश का हिस्सा थी। घटना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी। ढाबे के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावर की पहचान की जा सके और उसके भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके।

इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोग इस बात से हैरान हैं कि खुलेआम इस तरह की फायरिंग कैसे हो सकती है और अपराधी इतनी आसानी से फरार कैसे हो गया। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो हर एंगल से जांच कर रही हैं। राहुल के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, उसके दुश्मनों और हाल के विवादों की भी गहराई से पड़ताल की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि अपराध की दुनिया में दुश्मनी कितनी गहरी और खतरनाक हो सकती है। एक बार जब कोई व्यक्ति इस रास्ते पर कदम रखता है, तो उसके लिए सामान्य जीवन में लौटना बेहद मुश्किल हो जाता है। पुराने दुश्मन, अधूरे हिसाब और बदले की भावना उसे बार-बार हिंसा के चक्र में खींच लाते हैं। राहुल के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां उसका आपराधिक अतीत अब उसकी जान के लिए खतरा बन गया है।

चुनावी निष्पक्षता पर सख्ती-टीएमसी प्रचार के आरोप में एआरओ सस्पेंड, चुनाव आयोग का बड़ा संदेश

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी माहौल जहां धीरे-धीरे गरमाता जा रहा है, वहीं चुनाव आयोग की सख्ती भी अब साफ तौर पर नजर आने लगी है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए ईस्ट बर्दवान जिले में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई न केवल एक व्यक्तिगत मामले तक सीमित है, बल्कि यह पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए एक स्पष्ट संदेश भी है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की पक्षपातपूर्ण भूमिका या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिस अधिकारी पर यह कार्रवाई हुई है, उनका नाम ज्योत्सना खातून है, जो खंडघोष डेवलपमेंट ब्लॉक में जॉइंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) के साथ-साथ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर (ARO) की जिम्मेदारी भी निभा रही थीं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खुलेआम तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। यह आरोप बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया में नियुक्त अधिकारी से पूरी निष्पक्षता और तटस्थता की अपेक्षा की जाती है। ऐसे में किसी अधिकारी का किसी राजनीतिक दल के पक्ष में सक्रिय दिखना चुनाव की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है।

चुनाव आयोग के सचिव सुजीत कुमार मिश्रा द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला को भेजे गए आधिकारिक पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि संबंधित अधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। आयोग ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए यह भी कहा कि उसके निर्देशों का तत्काल पालन किया जाए और 4 अप्रैल 2026 की सुबह 11 बजे तक इस पर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट भेजी जाए। इससे यह साफ हो जाता है कि आयोग इस तरह के मामलों में किसी भी प्रकार की देरी या ढिलाई को स्वीकार करने के मूड में नहीं है।

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है और चुनावी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोग पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि चुनाव के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह निष्पक्ष रहेंगे और किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। इसके बावजूद अगर कोई अधिकारी इस तरह का कदम उठाता है, तो यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ भी खिलवाड़ है।

चुनाव आयोग ने इस मामले के साथ-साथ एक और महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने रखा है, जो राज्य की प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने 27 अक्टूबर 2025 को स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) शुरू होने से लेकर 16 मार्च 2026 को चुनाव की घोषणा होने तक कुल 1,370 अधिकारियों का तबादला किया। इनमें 97 आईएएस, 146 आईपीएस, 1,080 पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस और 47 पश्चिम बंगाल पुलिस सर्विस के अधिकारी शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में किए गए तबादलों को लेकर पहले ही राजनीतिक हलकों में चर्चा थी, और अब चुनाव आयोग ने इसे सार्वजनिक कर इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है।

आयोग के एक अंदरूनी सूत्र के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा किए गए इन बड़े पैमाने के तबादलों से प्रशासनिक अस्थिरता और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे आयोग ने अपने स्तर पर सीमित संख्या में ट्रांसफर करके नियंत्रित करने की कोशिश की है। यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि चुनाव आयोग केवल नियमों के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरी चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित और संतुलित बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से हस्तक्षेप भी कर रहा है।

इसी बीच, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी कि राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसा-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने 'जीरो टॉलरेंस' नीति लागू की है। इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, अनियमितता या हिंसा को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस पूरे घटनाक्रम को व्यापक संदर्भ में देखें तो यह साफ हो जाता है कि चुनाव आयोग इस बार पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर बेहद सतर्क और गंभीर है। राज्य में पहले भी चुनावों के दौरान हिंसा और अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं, ऐसे में आयोग की यह सख्ती कहीं न कहीं उन आशंकाओं को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ज्योत्सना खातून के खिलाफ की गई कार्रवाई इसी नीति का हिस्सा मानी जा रही है, जहां एक उदाहरण पेश करके बाकी अधिकारियों को भी चेतावनी दी गई है।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह मामला काफी अहम है, क्योंकि इससे प्रशासनिक निष्पक्षता पर बहस तेज हो सकती है।

पूर्वांचल महोत्सव-9 में संस्कृति, चेतना और सृजन की धारा—माटी से जुड़कर राष्ट्र निर्माण का आह्वान

दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी दर्शन प्रांगण में आयोजित पूर्वांचल महोत्सव-9 केवल एक सांस्कृतिक आयोजन भर नहीं रहा, बल्कि यह उस जीवंत परंपरा का उत्सव बन गया जिसमें विचार, साधना और सृजन एक साथ प्रवाहित होते हैं। इस भव्य आयोजन में देशभर से आए गणमान्य लोगों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों और पूर्वांचल से जुड़े लोगों ने अपनी जड़ों से जुड़ने और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। मंच पर जब लोकसभा अध्यक्ष Om Birla ने अपने विचार रखे, तो पूरा वातावरण पूर्वांचल की सांस्कृतिक गहराई और आध्यात्मिक ऊंचाई के संदेश से गूंज उठा।

ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्वांचल केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जिसने सदियों से समाज को दिशा दी है। यहां की धरती ने न केवल संतों और विचारकों को जन्म दिया, बल्कि कला, साहित्य और सामाजिक सरोकारों के माध्यम से पूरे राष्ट्र को समृद्ध किया है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि पूर्वांचल की पहचान उसकी विविधता और जीवंतता में है, जहां हर रंग, हर परंपरा और हर विचार एक साथ मिलकर एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का निर्माण करते हैं। उनके शब्दों में यह स्पष्ट झलक रहा था कि आधुनिकता के इस दौर में भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर वरिष्ठ सांसद Jagdambika Pal ने भी पूर्वांचल की प्रतिभाओं की सराहना करते हुए कहा कि यहां की मिट्टी में जन्मे लोगों ने अपने बौद्धिक और रचनात्मक प्रयासों से देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि जब लक्ष्य स्पष्ट हों और संकल्प मजबूत हो, तो कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों को छू सकता है। उनके शब्द उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा थे, जो अपने सपनों को साकार करने की दिशा में प्रयासरत हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष Ram Bahadur Rai ने 'माटी' संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था लगातार अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण के माध्यम से पूर्वांचल की आकांक्षाओं को नया आकार दे रही है। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि माटी ने अपने दम पर एक पहचान बनाई है और आज वह एक ऐसी शक्ति बन चुकी है, जो समाज को जोड़ने और आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। वहीं माटी के संयोजक Asif Azmi ने घोषणा की कि संस्था जल्द ही दिल्ली-एनसीआर में एक भव्य पूर्वांचल सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने जा रही है, जो आने वाले समय में इस क्षेत्र की सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा।

उद्घाटन सत्र में दिल्ली सरकार के मंत्री Kapil Mishra ने पूर्वांचल की मिट्टी की विशेषता को रेखांकित करते हुए कहा कि यहां की धरती में एक अनोखी शक्ति है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देती है। उन्होंने माटी संस्था को उसी मिट्टी से उगा हुआ एक विशाल वृक्ष बताया, जिसकी छाया में हजारों लोग अपनी पहचान और संस्कृति से जुड़ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस संस्था से जुड़ें और इसके मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग करें।

कार्यक्रम का सबसे भावुक और गौरवपूर्ण क्षण वह रहा जब Om Birla ने पूर्वांचल की छह प्रतिष्ठित हस्तियों को 'माटी सम्मान-9' से सम्मानित किया। इनमें Faiz Ahmed Kidwai, Dr Praveen Kumar Singh, Prof Vandana Singh, Ravi Shankar Rai, Rajesh Singh Dayal और Shweta Tripathi जैसे नाम शामिल रहे। इन सभी ने अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देकर न केवल पूर्वांचल बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है।

कार्यक्रम में पूर्व सांसद Brij Bhushan Sharan Singh ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि पूर्वांचल की धरती ने हमेशा समाज को दिशा देने वाले विचारकों, देश की रक्षा करने वाले वीरों और मानवता का मार्ग दिखाने वाले संतों को जन्म दिया है। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति हमेशा भूमि से शक्ति, समृद्धि और प्रेरणा प्राप्त करने की बात करती है, और पूर्वांचल की यह पावन धरती उसी परंपरा को जीवंत बनाए हुए है।

इस महोत्सव के दौरान सांसद Rajiv Rai ने माटी संस्था की योजनाओं और उसके विज़न की चर्चा करते हुए कहा कि यह संस्था पूर्वांचल के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कला, संस्कृति और विकास के क्षेत्र में संस्था कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जो आने वाले समय में पूर्वांचल की पहचान को और मजबूत करेंगे।

संगीत सत्र के मुख्य अतिथि और नीति आयोग के पूर्व CEO Amitabh Kant ने इस आयोजन को एक सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि यह संस्था न केवल लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ रही है, बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसे आयोजन समाज में सांस्कृतिक जागरूकता और राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करेंगे।

पूर्वांचल महोत्सव-9 ने यह साबित कर दिया कि जब परंपरा और आधुनिकता का संगम होता है, तो एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। यह आयोजन केवल अतीत की स्मृतियों को संजोने का माध्यम नहीं था, बल्कि भविष्य के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम भी था। यहां प्रस्तुत हुए विचार, सम्मानित की गई प्रतिभाएं और साझा की गई योजनाएं इस बात का संकेत हैं कि पूर्वांचल की मिट्टी में आज भी वह शक्ति मौजूद है, जो न केवल व्यक्तित्व को गढ़ती है, बल्कि पूरे राष्ट्र को नई दिशा देने की क्षमता रखती है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

देवरिया विवाद पर सियासी संग्राम तेज, शलभमणि त्रिपाठी के समर्थन में उतरी सुभासपा, विपक्ष पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप

उत्तर प्रदेश की राजनीति में देवरिया सदर सीट से विधायक Shalabh Mani Tripathi को लेकर छिड़ा विवाद अब एक बड़े राजनीतिक टकराव का रूप लेता जा रहा है। आरोप-प्रत्यारोप के इस दौर में जहां विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है, वहीं सत्तापक्ष और सहयोगी दल खुलकर बचाव में उतर आए हैं। इसी कड़ी में Om Prakash Rajbhar की पार्टी सुभासपा ने भी विधायक के समर्थन में मोर्चा संभाल लिया है और पूरे मामले को राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित करार दिया है।

सुभासपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता Raghavendra Ram Dwivedi ने सामने आकर विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विधायक पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और इनके पीछे केवल राजनीतिक लाभ हासिल करने की मंशा काम कर रही है। उनके मुताबिक, बिना किसी ठोस साक्ष्य के इस तरह के आरोप लगाना न केवल लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि इससे जनता के बीच भ्रम फैलाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

इस पूरे विवाद के केंद्र में जिस तरह से समाजवादी पार्टी सक्रिय दिख रही है, उसे लेकर भी सुभासपा ने सवाल खड़े किए हैं। सपा प्रमुख Akhilesh Yadav के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए राघवेंद्र द्विवेदी ने कहा कि केवल आरोप लगाने से सच्चाई नहीं बदलती। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा नेतृत्व वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। उनके अनुसार, जनता अब इस तरह की राजनीति को समझने लगी है और केवल बयानबाजी के आधार पर कोई भी दल लंबे समय तक लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे व्यापक राजनीतिक रणनीति भी काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावी समीकरणों को देखते हुए हर दल अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा हुआ है। ऐसे में किसी भी मुद्दे को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना आम बात हो गई है। शलभमणि त्रिपाठी का मामला भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, जहां एक ओर विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं सत्तापक्ष और उसके सहयोगी इसे साजिश करार देकर जवाबी रणनीति अपना रहे हैं।

सुभासपा की ओर से यह भी साफ किया गया कि उनकी पार्टी हमेशा जनहित के मुद्दों पर काम करने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ खड़ी रहती है। राघवेंद्र द्विवेदी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की छवि को बिना प्रमाण के नुकसान पहुंचाना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस मामले में तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए और राजनीतिक लाभ के लिए माहौल बनाने से बचना जरूरी है।

इस पूरे घटनाक्रम में सोशल मीडिया की भूमिका भी अहम हो गई है। 'एक्स' जैसे प्लेटफॉर्म पर नेताओं के बयान और प्रतिक्रियाएं तेजी से वायरल हो रही हैं, जिससे यह मुद्दा और अधिक चर्चा में आ गया है। राघवेंद्र द्विवेदी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और इसे एक सुनियोजित अभियान बताया।

वहीं, दूसरी ओर विपक्ष अपने रुख पर कायम है और लगातार इस मामले को उठाने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वे केवल जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं और यदि आरोप गलत हैं तो सरकार को स्पष्ट रूप से स्थिति सामने रखनी चाहिए। इस तरह दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है, जिससे राजनीतिक माहौल और अधिक गर्माता जा रहा है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तरह के विवाद कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से विभिन्न दलों ने खुलकर पक्ष और विपक्ष में मोर्चा संभाला है, वह इसे और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। खासतौर पर तब, जब राज्य की राजनीति में गठबंधन और समीकरण लगातार बदल रहे हों। सुभासपा का खुलकर समर्थन करना भी इसी बात का संकेत है कि सहयोगी दल इस मुद्दे पर एकजुट होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं।

आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या इसमें कोई ठोस तथ्य सामने आते हैं या फिर यह केवल राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाता है। फिलहाल इतना जरूर है कि देवरिया का यह मामला अब राज्य की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

कुल मिलाकर, यह घटनाक्रम एक बार फिर यह दर्शाता है कि राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर कितना तेज और प्रभावशाली हो सकता है। जहां एक ओर यह लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा है, वहीं दूसरी ओर यह जरूरी भी हो जाता है कि सच्चाई और तथ्यों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि जनता के बीच सही संदेश पहुंचे और लोकतंत्र की मूल भावना कायम रह सके।

निगला हुआ सबूत भी नहीं बचा सका आरोपी, बरेली में पुलिस की सूझबूझ से 3 दिन बाद बरामद हुआ चांदी का ब्रेसलेट

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से सामने आई एक अनोखी और हैरान कर देने वाली घटना ने यह साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न कर ले, कानून के शिकंजे से बच पाना आसान नहीं होता। बारादरी थाना क्षेत्र में चोरी के एक मामले में आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए ऐसा कदम उठाया, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी—उसने चोरी किया हुआ चांदी का ब्रेसलेट ही निगल लिया। लेकिन पुलिस की सतर्कता और डॉक्टरों की समझदारी के आगे उसकी यह चालाकी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और आखिरकार तीन दिन बाद वही ब्रेसलेट बरामद कर लिया गया।

पूरा मामला बारादरी क्षेत्र के हजियापुर इलाके का है, जहां रहने वाला सिकंदर उर्फ छोटू अपने साथी मुकेश के साथ एक घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था। दोनों ने बड़ी चालाकी से छत के रास्ते घर में प्रवेश किया और वहां से एक बुलेट बाइक के साथ करीब 42 ग्राम वजन का चांदी का ब्रेसलेट चोरी कर लिया। घटना के दौरान घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी गतिविधियां रिकॉर्ड हो गईं। हालांकि फुटेज में उनके चेहरे स्पष्ट नहीं दिख रहे थे, लेकिन पुलिस ने तकनीकी जांच और स्थानीय इनपुट के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बना ली।

जब पुलिस ने सिकंदर को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की, तो उसने अपनी चालाकी दिखाते हुए ऐसा कदम उठाया, जिसने पूरे मामले को और जटिल बना दिया। उसने चोरी किया हुआ ब्रेसलेट निगल लिया, ताकि उसके खिलाफ कोई

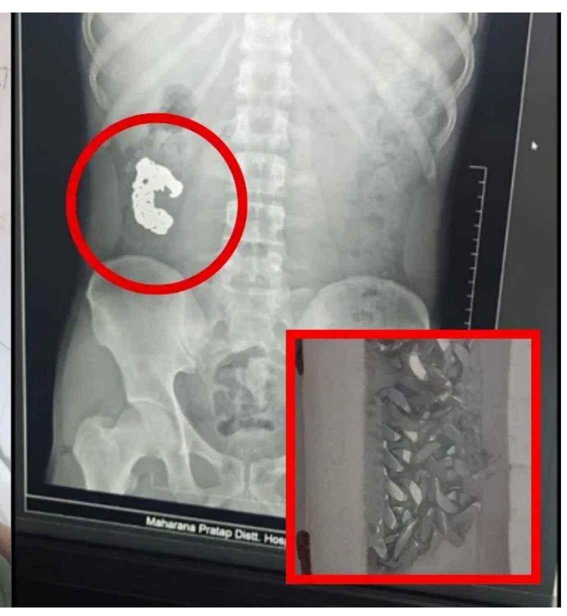

ठोस सबूत न बचे। उसे यह भरोसा था कि बिना बरामदगी के पुलिस उसके खिलाफ मजबूत केस नहीं बना पाएगी। लेकिन पुलिस ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तुरंत मेडिकल जांच का सहारा लिया। आरोपी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका एक्स-रे कराया गया। जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखा कि ब्रेसलेट उसके पेट में मौजूद है। इसके बाद पुलिस और डॉक्टरों के सामने चुनौती यह थी कि इस ब्रेसलेट को सुरक्षित तरीके से बाहर कैसे निकाला जाए। डॉक्टरों ने सलाह दी कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और इसे प्राकृतिक तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आरोपी का शौच जाना जरूरी था।

यहीं से शुरू हुआ एक अजीब और चुनौतीपूर्ण इंतजार। सिकंदर ने अपनी चालाकी जारी रखते हुए लगातार दो दिनों तक शौच जाने से बचने की कोशिश की। पुलिस ने उसे उसकी पसंद का खाना तक दिया, ताकि वह जल्द से जल्द शौच के लिए जाए और ब्रेसलेट बरामद हो सके, लेकिन वह हर बार बहाना बनाकर इसे टालता रहा। इस दौरान पुलिस के लिए यह मामला एक तरह की मानसिक जंग बन गया, जहां आरोपी हर संभव कोशिश कर रहा था कि सबूत बाहर न आ सके।

आखिरकार पुलिस ने नई रणनीति अपनाई। पहले आरोपी को जेल भेजा गया और फिर कोर्ट को पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए दोबारा जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों की सलाह पर उसे पेट साफ करने की दवा दी गई। इस बार दवा का असर जल्दी हुआ और कुछ ही समय में उसे शौच की जरूरत महसूस हुई। पुलिस पहले से पूरी तैयारी में थी। उसे अस्पताल के एक सुरक्षित और एकांत स्थान पर ले जाया गया, जहां सफाईकर्मियों की मदद से पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी गई।

करीब आधे घंटे बाद वह क्षण आया, जिसका पुलिस को इंतजार था। शौच के दौरान चांदी का ब्रेसलेट बाहर आ गया और पुलिस ने उसे सावधानीपूर्वक बरामद कर लिया। इसके बाद ब्रेसलेट को अच्छी तरह साफ किया गया और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे सबूत के रूप में मालखाने में जमा कर दिया गया। इस तरह आरोपी की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और पुलिस ने एक महत्वपूर्ण साक्ष्य हासिल कर लिया।

यह घटना न केवल अपराध की दुनिया में बढ़ती चालाकियों को उजागर करती है, बल्कि पुलिस और मेडिकल टीम के समन्वय का भी एक बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। यदि पुलिस केवल आरोपी के बयान पर निर्भर रहती या जल्दबाजी में कोई कठोर कदम उठाती, तो यह सबूत शायद कभी बरामद नहीं हो पाता। लेकिन धैर्य, रणनीति और वैज्ञानिक तरीके से काम करते हुए उन्होंने यह साबित कर दिया कि कानून का दायरा कितना व्यापक और प्रभावी हो सकता है।

अब इस मामले में पुलिस के पास न केवल सीसीटीवी फुटेज जैसे तकनीकी साक्ष्य हैं, बल्कि बरामद हुआ ब्रेसलेट भी एक मजबूत सबूत के रूप में मौजूद है। इससे आरोपी के खिलाफ केस और मजबूत हो गया है और उसे सख्त सजा दिलाने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चाहे अपराधी कितनी भी चतुराई दिखाए, कानून के सामने उसकी हर कोशिश अंततः विफल ही होती है।

बरेली की यह घटना अपने आप में अनोखी जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा संदेश छिपा है—अपराध का रास्ता भले ही कुछ समय के लिए आसान लगे, लेकिन अंततः सच्चाई सामने आ ही जाती है। सिकंदर की चालाकी ने कुछ समय के लिए पुलिस को जरूर उलझाया, लेकिन अंत में कानून की पकड़ उससे कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुई।

प्रेम, विश्वासघात और खून मेरठ में 'मुस्कान' जैसी एक और कहानी, जहां पत्नी ने प्रेमी संग रचा फौजी पति का कत्ल

उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई यह दिल दहला देने वाली घटना रिश्तों के उस काले सच को उजागर करती है, जहां प्रेम, लालच और विश्वासघात मिलकर इंसान को हैवानियत की हद तक पहुंचा देते हैं। एक बीएसएफ जवान, जो देश की सरहदों की रक्षा करता था, उसे अपने ही घर में, अपनी ही पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतरवा दिया। यह कहानी किसी फिल्मी साजिश से कम नहीं, लेकिन इसकी हकीकत बेहद खौफनाक है।

मामला मेरठ जिले का है, जहां नैन सिंह नाम का जवान बीएसएफ में तैनात था। ड्यूटी के कारण वह अक्सर घर से दूर रहता था, लेकिन जब भी छुट्टी पर आता, तो घर में सुकून तलाशता था। उसे शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस घर को वह अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना मानता है, वहीं उसकी जिंदगी की आखिरी सांसें लिखी जा रही हैं।

नैन सिंह की पत्नी कोमल काफी समय से उससे अलग रह रही थी। दोनों के बीच रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण थे और कई बार झगड़े भी हो चुके थे। इसी दौरान कोमल की नजदीकियां उसके ही मौसेरे भाई गुलशन से बढ़ गईं। यह रिश्ता धीरे-धीरे अवैध संबंधों में बदल गया। नैन सिंह को इस संबंध पर शक भी था, लेकिन वह इस साजिश की गहराई को समझ नहीं पाया। कोमल और गुलशन के बीच यह संबंध इतना गहरा हो चुका था कि उन्होंने नैन सिंह को अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा मान लिया। दोनों ने मिलकर उसे हमेशा के लिए हटाने की साजिश रची। इस साजिश की सबसे खौफनाक बात यह थी कि इसमें न सिर्फ योजना बनाई गई, बल्कि हर कदम को बेहद सोच-समझकर अंजाम दिया गया।

पुलिस जांच में सामने आया कि कोमल ने अपने जेवर—सोना—गिरवी रखकर गुलशन को पैसे दिए, ताकि वह तमंचा खरीद सके। इस एक कदम ने यह साफ कर दिया कि यह हत्या कोई आवेश में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि पूरी तरह से पूर्व नियोजित अपराध था। तमंचा खरीदने के बाद गुलशन ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी योजना को अंतिम रूप दिया।

घटना वाली रात, जब नैन सिंह अपने घर में सो रहा था, तब गुलशन और उसके साथियों ने मौके का फायदा उठाया। गहरी नींद में सो रहे नैन सिंह को गोली मार दी गई। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया—एक पति, एक जवान और एक भरोसेमंद रिश्ता। यह हत्या इतनी सुनियोजित थी कि पहली नजर में किसी को भी शक न हो।

हत्या के बाद कोमल ने खुद को बचाने के लिए एक और चाल चली। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए तहरीर में पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगा दिया, ताकि जांच की दिशा भटक जाए। कुछ समय के लिए यह चाल कामयाब होती दिखी, लेकिन कहते हैं कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता।

मेरठ पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल्स और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए पुलिस धीरे-धीरे असली आरोपियों तक पहुंच गई। जब कोमल से सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसकी कहानी में विरोधाभास सामने आने लगे। अंततः पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके प्रेमी गुलशन समेत अन्य साथियों को भी हिरासत में ले लिया।

पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जैसे ही इस पूरे मामले का खुलासा मीडिया के सामने किया गया, कोमल की मानसिक स्थिति बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। यह दृश्य इस बात का प्रतीक था कि अपराध का बोझ अंततः इंसान को तोड़ ही देता है। इस पूरे मामले पर एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि नैन सिंह बीएसएफ का जवान था और उसकी पत्नी का अवैध संबंध उसके मौसेरे भाई गुलशन से था। दोनों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या को अंजाम दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए पड़ोसियों को फंसाने की कोशिश की। उन्होंने यह भी बताया कि इस केस के खुलासे में ट्रेनी अधिकारी बजरंग प्रकाश और स्वाट टीम की अहम भूमिका रही। उनके सराहनीय कार्य के लिए पूरी टीम को 25,000 रुपये का नकद इनाम भी दिया गया। मेरठ की यह घटना केवल एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि यह समाज के उस खतरनाक मोड़ की ओर इशारा करती है, जहां रिश्तों में विश्वास की जगह शक, लालच और स्वार्थ ने ले ली है।

शौक नवाबों जैसे, रास्ता अपराध का... हापुड़ में लग्जरी लाइफस्टाइल की चाह ने भाई-बहन को बनाया चोर, पड़ोसी सहेली निकली मास्टरमाइंड

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से सामने आई यह सनसनीखेज वारदात एक बार फिर यह साबित करती है कि जब इंसान अपनी हैसियत से बड़ी जिंदगी जीने की चाहत पाल लेता है, तो वह सही-गलत की सीमाएं भूल बैठता है। थाना देहात क्षेत्र की इंद्रलोक कॉलोनी में हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने जो कहानी सामने रखी, वह किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है—जहां भरोसा, लालच और चालाकी तीनों ने मिलकर एक बड़े अपराध को जन्म दिया।

यह पूरा मामला 24 मार्च का है, जब इंद्रलोक कॉलोनी निवासी टिंबर व्यापारी कुलदीप गोयल के घर दिनदहाड़े चोरी की वारदात हुई। उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि व्यापारी की मां और पत्नी मोनिका गोयल महज एक घंटे के लिए प्राचीन सिद्धपीठ चंडी मंदिर दर्शन करने गई थीं। इसी छोटे से अंतराल का फायदा उठाते हुए चोरों ने घर का ताला खोला और अंदर रखी अलमारी व तिजोरी को निशाना बनाया। देखते ही देखते करीब आठ लाख रुपये की नकदी और सोने-चांदी के कीमती जेवरात गायब कर दिए गए।

जब घर की महिलाएं वापस लौटीं तो सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी-तिजोरी खाली थीं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शुरू में यह मामला एक सामान्य चोरी जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे-जैसे पुलिस ने परतें खोलनी शुरू कीं, कहानी में एक के बाद एक चौंकाने वाले

खुलासे सामने आते गए।

पुलिस ने सबसे पहले आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और इलाके में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। तकनीकी जांच और मुखबिर तंत्र के सहारे धीरे-धीरे शक की सुई कुछ ऐसे लोगों की ओर घूमने लगी, जिन पर शुरुआत में किसी को जरा भी संदेह नहीं था। जांच में सामने आया कि इस पूरी वारदात की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि व्यापारी के घर की पड़ोसी और उनकी पत्नी की करीबी सहेली ईशा गुप्ता थी। ईशा का कुलदीप गोयल के घर आना-जाना लगा रहता था। इसी दौरान उसने घर के भीतर की व्यवस्थाओं को बारीकी से समझ लिया था। उसे यह भी पता चल गया था कि घर की चाबियां कहां छिपाकर रखी जाती हैं। यही जानकारी बाद में इस बड़ी चोरी की सबसे अहम कड़ी साबित हुई। ईशा ने अपनी सहेली शालिनी उर्फ शालू के साथ मिलकर इस वारदात की पूरी साजिश रची। योजना के तहत शालिनी ने अपने भाई आकाश और मन्नू को भी इस 'आसान पैसे' के लालच में शामिल कर लिया। पहले से रेकी करने की उनकी आदत ने इस अपराध को और आसान बना दिया। भाई-बहन पहले कॉलोनियों में घूमकर घरों की निगरानी करते, लोगों की दिनचर्या समझते और फिर सही मौके का इंतजार करते थे। 24 मार्च को जब उन्हें पता चला कि घर की महिलाएं मंदिर गई हैं और घर खाली है, तो उन्होंने तुरंत अपने प्लान को अंजाम दे दिया।

पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दोयमी धनौरा बाइपास के पास घेराबंदी कर ईशा गुप्ता, शालिनी उर्फ शालू और आकाश को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चोरी के सोने-चांदी के आभूषण, 11 हजार रुपये नकद, आधार कार्ड और बैंक पासबुक बरामद की गई। पूछताछ में आरोपियों ने बिना ज्यादा देर लगाए अपना जुर्म कबूल कर लिया।

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि आरोपी पेशे से कोई बड़े अपराधी नहीं थे। वे शादियों में मेकअप और मेहंदी का काम करते थे, लेकिन उनकी इच्छाएं उनकी आय से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। ब्रांडेड कपड़े पहनने, महंगे मोबाइल रखने और लग्जरी लाइफ जीने की चाहत ने उन्हें इस रास्ते पर धकेल दिया। धीरे-धीरे यह चाहत लालच में बदली और लालच ने उन्हें अपराधी बना दिया।

इस पूरे मामले में एक और अहम किरदार मन्नू का है, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के अनुसार, वही वह व्यक्ति था जिसने घर के अंदर घुसकर तिजोरी और अलमारी को खंगाला था। उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

यह घटना केवल एक चोरी की वारदात नहीं है, बल्कि समाज के उस बदलते चेहरे को भी उजागर करती है, जहां दिखावे और भौतिक सुख-सुविधाओं की होड़ ने लोगों को गलत रास्तों की ओर धकेलना शुरू कर दिया है। भरोसे का रिश्ता, जो कभी सबसे मजबूत माना जाता था, वही यहां सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। एक पड़ोसी और करीबी सहेली ने ही घर की जानकारी का गलत फायदा उठाकर अपराध को अंजाम दिया।

फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। इस मामले ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि अपराध चाहे कितना भी योजनाबद्ध क्यों न हो, कानून की पकड़ से बच पाना आसान नहीं है।

नाई की दुकान से चल रही थी आतंकी साजिश, ATS ने ऐन वक्त पर तोड़ा मॉड्यूल; रेलवे सिग्नल बॉक्स उड़ाने से पहले 4 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आतंकी साजिश को ऐन वक्त पर नाकाम कर सुरक्षा एजेंसियों ने न सिर्फ एक गंभीर खतरे को टाल दिया, बल्कि यह भी उजागर कर दिया कि किस तरह साधारण जिंदगी की आड़ में देशविरोधी गतिविधियों का जाल बुना जा रहा था। यूपी एटीएस की सतर्कता और सटीक कार्रवाई ने एक ऐसे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर देश में दहशत फैलाने की बड़ी साजिश रच रहा था। यह गिरोह रेलवे के महत्वपूर्ण ढांचे को निशाना बनाने के साथ-साथ गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों में आगजनी कर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की फिराक में था।

इस पूरे ऑपरेशन का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इसका मुख्य आरोपी साकिब उर्फ वकिल, जो पेशे से एक साधारण नाई था, अपनी दुकान के जरिए ही इस साजिश का नेटवर्क चला रहा था। दिखने में आम जिंदगी जीने वाला यह युवक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स—टेलीग्राम, सिग्नल और इंस्टाग्राम—के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स से लगातार संपर्क में था। वहीं से उसे निर्देश, टारगेट और फंडिंग मिल रही थी।

यूपी एटीएस के अनुसार, 2 अप्रैल 2026 को लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास स्थित सिग्नल बॉक्स को आगजनी और विस्फोट से उड़ाने की योजना को अंजाम देने से ठीक पहले साकिब और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई बेहद गोपनीय इनपुट और लगातार निगरानी के बाद की गई, जिससे एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया।

जांच में सामने आया कि पाकिस्तानी हैंडलर्स आरोपी को कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित करने के लिए ओसामा बिन लादेन, फरहतुल्ला गौरी, कश्मीर मुजाहिद्दीन और 'गजवा-ए-हिंद' जैसे नामों का इस्तेमाल करते थे। इन नामों के जरिए साकिब और उसके साथियों को यह विश्वास दिलाया जाता था कि वे किसी 'बड़े मिशन' का हिस्सा हैं। धीरे-धीरे यह मानसिक रूप से उन्हें इस कदर प्रभावित कर गया कि उन्होंने देश की सार्वजनिक संपत्तियों और आम नागरिकों को निशाना बनाने की योजना बना डाली।

इस मॉड्यूल का काम करने का तरीका बेहद सुनियोजित और खतरनाक था। आरोपी पहले गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ जैसे शहरों में महत्वपूर्ण संस्थानों, रेलवे संपत्तियों और कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के घरों की रेकी करते थे। वे इन स्थानों के वीडियो बनाकर अपने हैंडलर्स को भेजते थे। इसके बाद हैंडलर्स गूगल लोकेशन के जरिए टारगेट फाइनल करते और हमले की रणनीति तय की जाती।

इतना ही नहीं, गिरोह ने अपनी 'टेस्ट रन' के तौर पर कुछ छोटी आगजनी की घटनाओं को अंजाम भी दिया था, जिनके वीडियो पाकिस्तान भेजे गए थे, ताकि हैंडलर्स को उनकी 'क्षमता' का अंदाजा हो सके। हर 'मिशन' के बाद आरोपियों को QR कोड के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जाते थे, जिससे यह नेटवर्क डिजिटल और गुप्त दोनों तरह से संचालित हो रहा था।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में साकिब उर्फ वकिल (मेरठ), अरबाब (मेरठ), विकास गहलावत उर्फ रौनक (गौतम बुद्ध नगर) और लोकेश उर्फ पपला पंडित (गौतम बुद्ध नगर) शामिल हैं। इनके पास से एक कैन ज्वलनशील पदार्थ, सात स्मार्टफोन, 24 पर्चे और पहचान संबंधी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ये सभी चीजें इस बात का संकेत देती हैं कि गिरोह न सिर्फ योजनाएं बना रहा था, बल्कि उन्हें जल्द ही बड़े स्तर पर अंजाम देने वाला था।

एटीएस ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं—148, 152, 61(2)—के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 13 और 18 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह धाराएं देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की साजिश और आतंकी गतिविधियों से सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं, जो इस पूरे मामले की गंभीरता को दर्शाती हैं। सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में यह भी सामने आया है कि यह गिरोह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हैंडलर्स के संपर्क में था और भारत में बड़े स्तर पर हिंसा, आगजनी और यहां तक कि सामूहिक नरसंहार जैसी घटनाओं की योजना बना रहा था। यदि यह साजिश समय रहते नाकाम नहीं होती, तो इसके परिणाम बेहद भयावह हो सकते थे।

यह घटना सिर्फ एक आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ की कहानी नहीं है, बल्कि यह आधुनिक दौर में बदलते खतरों की भी एक चेतावनी है—जहां सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल युवाओं को गुमराह करने और उन्हें देशविरोधी गतिविधियों में धकेलने के लिए किया जा रहा है। एक साधारण नाई की दुकान से शुरू हुआ यह नेटवर्क यह दिखाता है कि खतरा अब पारंपरिक सीमाओं से कहीं आगे बढ़ चुका है। यूपी एटीएस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा एजेंसियां हर स्तर पर सतर्क हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में भी अभियान तेज कर दिया गया है, ताकि इस तरह की किसी भी साजिश को जड़ से खत्म किया जा सके।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com* navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

ग्रेटर नोएडा में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक, पूर्व रक्षा मंत्रालय अधिकारी पर हमला; 13 जगहों पर काटा, सोसाइटी में दहशत

ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली क्षेत्र स्थित अजनारा पनोरमा सोसाइटी से सामने आई यह घटना सिर्फ एक हमले की खबर नहीं, बल्कि शहरी लापरवाही, प्रशासनिक ढिलाई और बढ़ते असंतुलन की एक गंभीर तस्वीर है। जिस शहर को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर जीवनशैली के लिए जाना जाता है, वहीं अब लोग अपने ही घरों के बाहर सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। शुक्रवार सुबह घटी इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया, जब रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी डॉ. दीर्घ नारायण पर एक आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया और उन्हें 13 जगहों पर काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

डॉ. दीर्घ नारायण कोई आम नागरिक नहीं हैं। वह 1977 बैच के सिविल सेवा अधिकारी रह चुके हैं और लगभग 27 वर्षों तक देश के रक्षा मंत्रालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद अब वह शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन पर हमला हुआ, उसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज के शहरी समाज में बुजुर्ग और आम नागरिक वास्तव में सुरक्षित हैं?

घटना शुक्रवार सुबह की है। रोज की तरह डॉ. नारायण अपनी पत्नी के साथ सोसाइटी परिसर में टहलने निकले थे। सुबह का समय, शांत माहौल और नियमित दिनचर्या—सब कुछ सामान्य था। लेकिन अचानक एक आवारा कुत्ता तेजी से उनकी ओर झपटा और बिना किसी उकसावे के उन पर हमला कर दिया। पहले तो डॉ. नारायण को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में स्थिति भयावह हो गई। कुत्ता बेहद आक्रामक था और लगातार उन पर झपटता रहा। डॉ. नारायण ने खुद को बचाने की हर संभव कोशिश की—हाथों से रोकने की कोशिश, पीछे हटने की कोशिश—लेकिन कुत्ते का हमला लगातार जारी रहा। इस दौरान उनकी पत्नी ने भी साहस दिखाते हुए कुत्ते को भगाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी इस हमले को रोकने में असफल रहीं। कुत्ते ने उनके हाथ, पैर और शरीर

के कई हिस्सों पर काट लिया। कुल मिलाकर 13 जगहों पर गहरे घाव हो गए, जिससे खून बहने लगा और उनकी हालत बिगड़ने लगी।

घटना के दौरान जब उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई, तब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। काफी प्रयासों के बाद कुत्ते को वहां से भगाया जा सका। इसके बाद घायल अवस्था में डॉ. नारायण को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया और उन्हें भर्ती कर लिया। डॉक्टरों के अनुसार, उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन गहरे घावों के कारण संक्रमण का खतरा बना हुआ है, इसलिए उन्हें निगरानी में रखा गया है।

यह घटना यहीं खत्म नहीं होती। इसके पीछे एक लंबी कहानी है—सोसाइटी में लंबे समय से आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और प्रशासन की अनदेखी। अजनारा पनोरमा सोसाइटी में करीब 50 परिवार रहते हैं, और यहां के निवासियों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है। पिछले कई महीनों से लोग इस मुद्दे को लेकर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिला, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

निवासियों का आरोप है कि यमुना प्राधिकरण और संबंधित एजेंसियों को कई बार लिखित और मौखिक शिकायत दी गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनका टीकाकरण करने और उन्हें शेल्टर होम भेजने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, वह या तो बेहद धीमी है या फिर बिल्कुल प्रभावी नहीं है। परिणामस्वरूप, कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और उनके व्यवहार में आक्रामकता भी देखने को मिल रही है।

इस घटना के बाद सोसाइटी में डर का माहौल साफ महसूस किया जा सकता है। बच्चे अब बाहर खेलने से डर रहे हैं, बुजुर्ग टहलने से बच रहे हैं और महिलाएं भी अकेले बाहर निकलने में हिचकिचा रही हैं। लोगों का कहना है कि अगर एक वरिष्ठ नागरिक, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, इस तरह हमले का शिकार हो सकता है, तो बाकी लोगों की सुरक्षा की क्या गारंटी है?

यह घटना प्रशासनिक जिम्मेदारी पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। शहरों में बढ़ती आबादी के साथ-साथ पशु प्रबंधन की व्यवस्था को भी उतनी ही तेजी से विकसित किया जाना चाहिए था, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। आवारा कुत्तों की समस्या अब केवल एक 'छोटी परेशानी' नहीं रही, बल्कि यह सार्वजनिक सुरक्षा का मुद्दा बन चुकी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या का समाधान केवल कुत्तों को पकड़ने तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक व्यापक और मानवीय नीति की जरूरत है—जिसमें नसबंदी, टीकाकरण, शेल्टर होम की व्यवस्था और लोगों में जागरूकता शामिल हो। लेकिन जब तक इन योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी।

फिलहाल, डॉ. दीर्घ नारायण अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं और उनकी स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। वहीं सोसाइटी के लोग प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर काम दिखाई देना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना दोबारा न हो।

ग्रेटर नोएडा की यह घटना एक चेतावनी है—अगर समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह खतरा और बढ़ सकता है। और तब शायद किसी और को इसकी कीमत अपनी जान या गंभीर चोटों के रूप में चुकानी पड़े।

शादी में शामिल होना पड़ा भारी संभल SP के रिसेप्शन पर सपा में सियासी हलचल, अखिलेश की नाराजगी के बाद सफाई और सख्त चेतावनी

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक शादी समारोह ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा कर दिया, जिसने समाजवादी पार्टी के अंदर अनुशासन, राजनीतिक मर्यादा और जमीनी हकीकत के बीच चल रहे टकराव को खुलकर सामने ला दिया। संभल के पुलिस अधीक्षक केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा के शादी समारोह में सपा के कई नेताओं और विधायकों की मौजूदगी ने पार्टी के भीतर असहज स्थिति पैदा कर दी, जिसका असर सीधे पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की नाराजगी के रूप में सामने आया।

जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया, तो अखिलेश यादव ने स्पष्ट और सख्त लहजे में कहा कि पार्टी के नेताओं को ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था और सभी को समझाया जाएगा। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। यह सिर्फ एक सामान्य नाराजगी नहीं थी, बल्कि इसे पार्टी अनुशासन से जोड़कर देखा जाने लगा। पार्टी के अंदर यह संदेश गया कि संगठन की लाइन से हटकर कोई भी कदम उठाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दरअसल, इस पूरे विवाद की जड़ में केवल एक शादी समारोह नहीं, बल्कि उससे जुड़ा राजनीतिक संदर्भ है। संभल के एसपी केके बिश्नोई पर पहले से ही अल्पसंख्यक समुदाय और समाजवादी पार्टी से जुड़े कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में जब सपा के ही नेता उनके निजी समारोह में शामिल होते दिखे, तो यह पार्टी कार्यकर्ताओं और खासकर अल्पसंख्यक वर्ग के बीच गलत संदेश देने वाला माना गया। यही वजह रही कि यह मुद्दा तेजी से संवेदनशील बन गया।

पार्टी की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जहां अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि पार्टी की विचारधारा और लाइन का पालन हर नेता के लिए अनिवार्य है। उन्होंने यह संकेत भी दिया कि यदि भविष्य में इस तरह की अनुशासनहीनता दोहराई गई, तो कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। उनके इस रुख ने पार्टी के भीतर एक स्पष्ट संदेश दिया—व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर संगठन की नीति है।

हालांकि, इस सख्त रुख के बाद सपा नेताओं और विधायकों ने भी अपना पक्ष सामने रखा। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को समझाने की कोशिश की कि स्थानीय स्तर की राजनीति में परिस्थितियां अलग होती हैं। उनका कहना था कि उन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से तालमेल बनाकर रखना पड़ता है। अगर वे पूरी तरह दूरी बना लें, तो जनता के काम प्रभावित हो सकते हैं।

नेताओं ने यह भी तर्क दिया कि शादी जैसे कार्यक्रम सामाजिक होते हैं, न कि राजनीतिक। ऐसे आयोजनों में शामिल होना शिष्टाचार का हिस्सा माना जाता है और इसे राजनीतिक समर्थन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उनका कहना था कि व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को पूरी तरह खत्म कर देना व्यावहारिक राजनीति में संभव नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, नेताओं की इस सफाई और व्यावहारिक मजबूरियों को देखते हुए अब सपा नेतृत्व ने किसी बड़े अनुशासनात्मक एक्शन से फिलहाल दूरी बना ली है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि मामला पूरी तरह खत्म हो गया है। पार्टी ने सभी संबंधित नेताओं को सख्त चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी कदम से पहले संगठन की लाइन और उसके राजनीतिक संदेश का ध्यान रखना अनिवार्य होगा।

इस पूरे घटनाक्रम ने समाजवादी पार्टी के भीतर एक अहम बहस को जन्म दिया है—क्या जमीनी राजनीति में काम करने वाले नेताओं के लिए पूरी तरह 'सख्त राजनीतिक लाइन' पर चलना संभव है, या फिर उन्हें कुछ हद तक सामाजिक और प्रशासनिक संतुलन बनाना पड़ता है? एक तरफ पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता है, तो दूसरी तरफ स्थानीय स्तर की व्यावहारिक मजबूरियां।

यह मामला इस बात का भी संकेत देता है कि आने वाले समय में सपा अपने संगठनात्मक ढांचे और अनुशासन को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठा सकती है। फिलहाल, पार्टी ने संतुलित रुख अपनाते हुए न तो कोई कड़ा एक्शन लिया है और न ही इस मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। चेतावनी देकर मामला शांत करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन अंदरूनी स्तर पर यह साफ कर दिया गया है कि आगे ऐसी गलती दोहराई गई, तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

अंततः, यह घटना केवल एक शादी समारोह में शामिल होने का विवाद नहीं है, बल्कि यह उस जटिल राजनीति की झलक है, जहां रिश्ते, जिम्मेदारियां और विचारधारा—तीनों के बीच संतुलन बनाना नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है।

आरओ-2023 पेपर लीक का बड़ा खुलासा: महीनों से फरार कृष्णा पांडेय वाराणसी से गिरफ्तार, STF अब नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने में जुटी

उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर लगातार उठते सवालों के बीच समीक्षा अधिकारी (आरओ) परीक्षा-2023 पेपर लीक प्रकरण में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपियों में शामिल कृष्णा पांडेय को आखिरकार उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी न केवल इस चर्चित मामले में एक अहम कड़ी मानी जा रही है, बल्कि इससे पूरे लीक नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद भी तेज हो गई है।

कृष्णा पांडेय के खिलाफ प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में पहले से ही एफआईआर दर्ज थी, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और परीक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। एसटीएफ के मुताबिक, आरोपी पिछले काफी समय से फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। आखिरकार पुख्ता सूचना मिलने के बाद उसे वाराणसी के अखरी बाईपास इलाके से दबोच लिया गया, जहां वह छिपकर रह रहा था।

इस पूरे मामले की जांच जब से एसटीएफ को सौंपी गई, तभी से कृष्णा पांडेय एजेंसियों के रडार पर था। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि वह सिर्फ एक मामूली कड़ी नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क में उसकी भूमिका काफी अहम रही है। यही कारण है कि उसकी गिरफ्तारी को इस केस में 'ब्रेकथ्रू' माना जा रहा है।

गौरतलब है कि इससे पहले इसी मामले में सह-आरोपी सुभाष प्रकाश और विवेक उपाध्याय को जून 2024 में गिरफ्तार किया जा चुका है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ही जांच एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले थे, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई तेज की गई। अब कृष्णा पांडेय के पकड़े जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पेपर लीक के पूरे सिंडिकेट की परतें और तेजी से खुलेंगी।

एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार, कृष्णा पांडेय की गिरफ्तारी एक सटीक खुफिया इनपुट के आधार पर संभव हो पाई। मुखबिर से मिली जानकारी के बाद टीम ने उसकी लोकेशन को ट्रैक किया और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान उसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन टीम की घेराबंदी के आगे वह ज्यादा देर टिक नहीं सका।

अब सबसे अहम चरण शुरू हो चुका है—पूछताछ। जांच एजेंसियां आरोपी से यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि पेपर लीक की साजिश किस स्तर पर और किन-किन लोगों की मिलीभगत से रची गई। यह भी पता लगाया जा रहा है कि प्रश्नपत्र लीक करने का तरीका क्या था, किन चैनलों के जरिए इसे अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया और इसके बदले कितनी रकम ली गई।

सूत्रों के अनुसार, इस नेटवर्क में केवल स्थानीय स्तर के लोग ही नहीं, बल्कि विभिन्न शहरों और संभवतः अन्य राज्यों तक फैला एक संगठित गिरोह शामिल हो सकता है। ऐसे मामलों में अक्सर तकनीकी माध्यमों, अंदरूनी लोगों और बिचौलियों का जाल होता है, जिसे तोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन एसटीएफ की टीम अब इसी दिशा में तेजी से काम कर रही है।

यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि आरओ जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में पेपर लीक की घटना ने हजारों मेहनती अभ्यर्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में सरकार और एजेंसियों पर दबाव था कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जाए।

कृष्णा पांडेय की गिरफ्तारी के बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि इस केस में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। जांच एजेंसियां इस एंगल से भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या इस नेटवर्क में कोई अधिकारी या परीक्षा से जुड़ा अंदरूनी व्यक्ति भी शामिल था, जिसने सिस्टम का दुरुपयोग कर पेपर बाहर पहुंचाया।

फिलहाल, आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं एसटीएफ की टीमें इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। यह गिरफ्तारी सिर्फ एक आरोपी की पकड़ नहीं, बल्कि उस विश्वास को बहाल करने की दिशा में एक कदम है, जो बार-बार होने वाले पेपर लीक मामलों से कमजोर पड़ा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच एजेंसियां इस पूरे रैकेट की जड़ तक पहुंचकर कितनी बड़ी सच्चाई सामने लाती हैं।

सैफई के खेत में गिरा ड्रोन बना सनसनी का कारण, तकनीकी खराबी ने मचाई दहशत; प्रशासन ने कहा-घबराने की जरूरत नहीं

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई क्षेत्र में शुक्रवार की शाम एक अप्रत्याशित घटना ने पूरे इलाके को कुछ समय के लिए भय और अफवाहों के साये में ला खड़ा किया। नंदपुर गांव के पास फैले गेहूं के हरे-भरे खेतों के बीच अचानक एक बड़ा ड्रोन आकर गिरा, जिसे देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। रोजमर्रा के कामकाज में व्यस्त लोग जब इस अनजान और असामान्य वस्तु को आसमान से गिरते हुए देखे, तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में डर और आशंका घर कर गई। देखते ही देखते खेत के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई।

ग्रामीणों के लिए यह दृश्य बिल्कुल नया और चौंकाने वाला था। किसी ने इसे किसी बड़ी साजिश से जोड़कर देखा तो किसी ने अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित होकर इसे सुरक्षा से जुड़ा खतरा मान लिया। हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट में ड्रोन हमलों की लगातार आ रही खबरों ने पहले ही लोगों के मन में एक अनजाना भय पैदा कर रखा है, ऐसे में इस तरह की घटना ने उस डर को और गहरा कर दिया। कई ग्रामीणों ने अपने परिवार के सदस्यों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा, जबकि कुछ लोग दूर से ही इस ड्रोन को देखने लगे।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम बिना देरी किए मौके पर पहुंच गई। प्रशासन ने हालात की गंभीरता को समझते हुए तुरंत पूरे क्षेत्र को घेर लिया और किसी भी आम नागरिक को ड्रोन के करीब जाने से रोक दिया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कदम बेहद जरूरी था, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि ड्रोन में किसी प्रकार का खतरनाक उपकरण या सामग्री तो नहीं है। अधिकारियों ने बड़ी सावधानी के साथ स्थिति का जायजा लिया और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की।

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि यह ड्रोन किसी प्रकार का परीक्षण (टेस्टिंग) ड्रोन है, जो तकनीकी खराबी के कारण नियंत्रण खो बैठा और खेत में गिर गया। हालांकि, प्रशासन ने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी संभावनाओं की गहन जांच करने का निर्णय लिया है। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम को भी इस ड्रोन की जांच के लिए लगाया गया है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि इसमें खराबी किस कारण से आई और यह किस संस्था या कंपनी से जुड़ा हुआ है।

इस बीच, प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीणों के बीच फैली अफवाहों को नियंत्रित करना रही। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तरह-तरह की बातें फैलानी शुरू कर दीं, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो सकती थी। इसे देखते हुए अधिकारियों ने मौके पर ही लोगों को समझाना शुरू किया और साफ शब्दों में बताया कि यह कोई सुरक्षा या आतंकी गतिविधि से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि एक सामान्य तकनीकी दुर्घटना है। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि इस मामले में कोई भी संदिग्ध पहलू सामने आता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, ड्रोन को कब्जे में लेकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया है और उसकी विस्तृत जांच जारी है।

यह घटना एक बार फिर इस बात की ओर इशारा करती है कि आधुनिक तकनीक जहां एक ओर सुविधाएं बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर इसके अप्रत्याशित जोखिम भी सामने आ रहे हैं। ड्रोन जैसी तकनीक का उपयोग आज कई क्षेत्रों में हो रहा है—चाहे वह कृषि हो, सर्वेक्षण हो या सुरक्षा। लेकिन जब ऐसी मशीनें नियंत्रण खो देती हैं, तो वे आम लोगों के लिए चिंता और भय का कारण बन सकती हैं।

सैफई के नंदपुर गांव में हुई यह घटना भले ही एक तकनीकी खराबी का परिणाम हो, लेकिन इसने यह जरूर दिखा दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी घटनाओं को लेकर जागरूकता की कमी है। यदि लोगों को पहले से इस तरह की तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाए, तो वे ऐसी स्थितियों में घबराने के बजाय समझदारी से काम ले सकते हैं।

फिलहाल, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और गांव में सामान्य जनजीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा है। प्रशासन की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाल दिया। अब सबकी नजर इस बात पर है कि तकनीकी जांच में क्या निष्कर्ष निकलता है और यह ड्रोन आखिर किस उद्देश्य से उड़ाया जा रहा था।

जौनपुर से उठी सियासी तल्खी: ओम प्रकाश राजभर का सपा पर बड़ा हमला, 'जमीनी भरोसा खत्म, पीडीए सिर्फ नारा बनकर रह गया'

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का तापमान बढ़ गया है, जहां जौनपुर की धरती से ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उसके सामाजिक समीकरण, नेतृत्व संरचना और चुनावी रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राजभर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान जिस तरह से सपा की कार्यप्रणाली को "विरोधाभासों से भरी" बताया, उसने प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है।

राजभर का सबसे बड़ा आरोप यही रहा कि सपा अब जमीनी स्तर पर अपना भरोसा खो चुकी है। उन्होंने कहा कि पार्टी का जो पारंपरिक सामाजिक आधार हुआ करता था, वह धीरे-धीरे खिसकता जा रहा है। खासतौर पर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति, जिसे सपा अपनी ताकत बताती रही है, अब केवल एक नारे तक सीमित रह गई है। राजभर के मुताबिक, यह अवधारणा व्यवहार में कहीं दिखाई नहीं देती और सिर्फ चुनावी मंचों तक सिमट कर रह गई है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने पार्टी के अंदरूनी ढांचे को भी कटघरे में खड़ा किया। उनका कहना था कि निर्णय लेने की प्रक्रिया कुछ सीमित लोगों तक सिमट गई है, जिससे व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में लोकतांत्रिक संवाद की कमी है और यही कारण है कि कई वर्ग खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं।

राजभर ने विशेष रूप से मुस्लिम नेतृत्व के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सपा के भीतर इस वर्ग की स्थिति पहले की तुलना में कमजोर हुई है। उनके अनुसार, पार्टी में मौजूद मुस्लिम नेता अपने अधिकारों और मुद्दों को लेकर खुलकर बोल नहीं पाते, जिससे यह संदेश जाता है कि नेतृत्व संतुलित नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब सपा खुद को अल्पसंख्यकों का मजबूत प्रतिनिधि बताती रही है, ऐसे में राजभर का यह आरोप राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है।

अपने आरोपों को और धार देते हुए राजभर ने सपा के पूर्व शासनकाल की नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उस समय अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अपेक्षित न्याय नहीं किया गया, जिससे असंतोष की स्थिति पैदा हुई। दादरी जैसे संवेदनशील मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी नेतृत्व द्वारा चुने गए मुद्दे और उनकी प्रस्तुति दोनों ही प्रभावी नहीं रहे, जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा।

राजभर का यह भी कहना था कि सपा की राजनीति अब स्पष्ट दिशा से भटक चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी का रुख कई महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर असंगत दिखाई देता है, जिससे जनता के बीच भ्रम की स्थिति बनती है। उनके मुताबिक, सपा की रणनीति में स्पष्टता का अभाव है और यही कमजोरी आने वाले चुनावों में उसके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है।

वोट बैंक की राजनीति को लेकर भी राजभर ने सपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी अब सिद्धांतों से ज्यादा वोटों के गणित पर निर्भर हो गई है। पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति तो की जाती है, लेकिन वास्तविक नीतियों और योजनाओं में इन वर्गों को वह महत्व नहीं मिल पाता, जिसकी अपेक्षा की जाती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान आरक्षण व्यवस्था और महापुरुषों से जुड़ी कई योजनाओं को नुकसान पहुंचाया गया।

राजभर ने दावा किया कि अब प्रदेश की जनता पहले से ज्यादा जागरूक हो चुकी है और वह केवल नारों या वादों के आधार पर निर्णय नहीं लेती। उनके अनुसार, आने वाले चुनावों में यही जागरूकता निर्णायक भूमिका निभाएगी और जो दल जमीनी हकीकत से दूर होगा, उसे नुकसान उठाना पड़ेगा।

'माननीय' शब्द पर हाईकोर्ट की सख्ती: एफआईआर की भाषा से उठे सवाल, सरकार से मांगा जवाब

प्रयागराज में एक दिलचस्प लेकिन महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा सामने आया है, जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक एफआईआर की भाषा को लेकर गंभीर रुख अपनाया है। मामला किसी बड़े अपराध से नहीं, बल्कि एक औपचारिक शब्द—'माननीय'—के इस्तेमाल या न इस्तेमाल से जुड़ा है, लेकिन अदालत ने इसे प्रशासनिक शिष्टाचार और प्रक्रिया की दृष्टि से अत्यंत अहम माना है। इसी कारण न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण तलब किया है।

यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब एक याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय की नजर एफआईआर में दर्ज एक केंद्रीय मंत्री के नाम पर पड़ी। अदालत ने पाया कि संबंधित मंत्री के नाम के साथ 'माननीय' या 'श्री' जैसे सम्मानसूचक शब्द नहीं जोड़े गए थे। इस पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने आश्चर्य व्यक्त किया और इसे एक साधारण चूक मानने के बजाय प्रशासनिक लापरवाही के रूप में देखा।

अदालत ने स्पष्ट कहा कि भले ही शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में किसी व्यक्ति का नाम बिना सम्मानसूचक शब्दों के लिखा हो, लेकिन जब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, तब उसकी जिम्मेदारी केवल तथ्यों को लिखना ही नहीं, बल्कि सरकारी प्रोटोकॉल और औपचारिकता का पालन सुनिश्चित करना भी होता है। न्यायालय के अनुसार, यह केवल भाषा का मामला नहीं, बल्कि संस्थागत मर्यादा और पद की गरिमा से जुड़ा प्रश्न है।

खंडपीठ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करें कि आखिर ऐसी त्रुटि कैसे हुई। अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस आदेश की जानकारी समयबद्ध तरीके से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचे, जिसके लिए रजिस्ट्रार (अनुपालन) को 48 घंटे के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

यह मामला मथुरा से जुड़े एक प्रकरण में दाखिल याचिका के दौरान उठा, जिसमें हर्षित शर्मा और दो अन्य याचिकाकर्ताओं ने आपराधिक धमकी और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित आरोपों को चुनौती दी है। इसी एफआईआर में केंद्रीय मंत्री का नाम भी शामिल था, और वहीं पर यह कथित त्रुटि सामने आई।

हालांकि पहली नजर में यह मुद्दा केवल औपचारिकता का लग सकता है, लेकिन न्यायालय ने इसे व्यापक प्रशासनिक अनुशासन और सरकारी कार्यप्रणाली से जोड़कर देखा है। अदालत का मानना है कि जब सरकारी दस्तावेजों में किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति का उल्लेख किया जाता है, तो उसमें तय प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। यह न केवल उस पद की गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी है, बल्कि इससे सरकारी व्यवस्था की पेशेवर गंभीरता भी झलकती है।

इस घटनाक्रम ने एक बड़ी बहस को जन्म दिया है कि क्या एफआईआर जैसे कानूनी दस्तावेजों में सम्मानसूचक शब्दों का उपयोग अनिवार्य होना चाहिए या नहीं। एक पक्ष का मानना है कि कानून के दस्तावेजों में सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखा जाना चाहिए और वहां किसी प्रकार की विशेष संबोधन की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरा पक्ष यह तर्क देता है कि सार्वजनिक जीवन में पद और जिम्मेदारी के अनुरूप औपचारिक सम्मान दिखाना भी प्रशासनिक संस्कृति का हिस्सा है।

न्यायालय ने फिलहाल इस बहस में सीधे तौर पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उसने यह जरूर संकेत दिया है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में शिष्टाचार और प्रोटोकॉल की अनदेखी स्वीकार्य नहीं है।

पुडुचेरी में चुनावी माहौल चरम पर: पीएम मोदी का मेगा रोड शो, जनसैलाब के बीच NDA ने झोंकी पूरी ताकत

पुडुचेरी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी तापमान अपने चरम पर पहुंच गया है, जहां नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो ने चुनावी माहौल को पूरी तरह से अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की। अंसारी दुरैसामी रोड से लेकर कामराज सलाई तक निकले इस भव्य रोड शो में सड़कों पर उमड़े जनसैलाब ने यह संकेत दे दिया कि चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा होने वाला है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों के दोनों ओर खड़े होकर प्रधानमंत्री का स्वागत करते नजर आए, जिससे पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल बन गया।

इस रोड शो में एन. रंगासामी, नमचिवयम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व उम्मीदवार माना रामलिंगम भी शामिल रहे। सभी नेताओं ने मिलकर शक्ति प्रदर्शन के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरा है और जीत को लेकर आश्वस्त है।

रोड शो से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की, जिसमें उन्होंने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि केवल भीड़ जुटाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस समर्थन को वोटों में बदलना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी के तहत उन्होंने 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' का नारा दोहराया और हर कार्यकर्ता से घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करने की अपील की।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पुडुचेरी के विकास को लेकर अपनी सोच भी साझा की। उन्होंने 'BEST' यानी व्यापार (Business), शिक्षा (Education), आध्यात्मिकता (Spirituality) और पर्यटन (Tourism) को विकास का आधार बताते हुए कहा कि यही चार स्तंभ पुडुचेरी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने पहली बार यह मंत्र दिया था, तब खासतौर पर युवाओं ने इसे काफी सराहा था और अब समय आ गया है कि इसे जमीनी हकीकत में बदला जाए।

चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस-डीएमके गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह गठबंधन जनहित से ज्यादा परिवारवाद की राजनीति को प्राथमिकता देता है। उनके अनुसार, जहां भाजपा-एनडीए का लक्ष्य 'पुडुचेरी सर्वोपरि, भारत सर्वोपरि' है, वहीं विपक्ष के लिए 'परिवार सर्वोपरि' है। इस बयान के जरिए उन्होंने चुनाव को वैचारिक लड़ाई के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन के भीतर आपसी मतभेद और संघर्ष यह दिखाते हैं कि वे सत्ता पाने के लिए तो एकजुट हो सकते हैं, लेकिन जनकल्याण के लिए उनकी कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे इन मुद्दों को जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखें, ताकि मतदाता सही निर्णय ले सकें।

इस रोड शो को केवल एक चुनावी कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। चुनाव से ठीक एक सप्ताह पहले इस तरह का आयोजन यह संकेत देता है कि भाजपा और एनडीए गठबंधन पुडुचेरी में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते।

सड़कों पर उमड़ी भीड़ और कार्यकर्ताओं के उत्साह ने यह जरूर दिखाया कि चुनावी मुकाबला अब पूरी तरह से तेज हो चुका है। हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और आखिरी समय में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बड़े-बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

फिलहाल, इस मेगा रोड शो ने भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश को मजबूती दी है, लेकिन अंतिम फैसला मतदाताओं के हाथ में है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह जनसैलाब वोटों में तब्दील हो पाता है या विपक्ष अपनी रणनीति से मुकाबले को संतुलित कर पाता है।

केरल बनाम तेलंगाना: पिनारयी विजयन का पलटवार 'बुलडोजर चलाने वाले हमें न सिखाएं विकास'

देश की राजनीति में एक नया वाकयुद्ध तब देखने को मिला जब पिनारयी विजयन ने रेवंत रेड्डी के बयानों पर तीखा जवाब देते हुए उन्हें सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए गए अपने विस्तृत बयान में विजयन ने न सिर्फ रेड्डी की टिप्पणियों को "पूरी तरह निराधार" बताया, बल्कि यह भी कहा कि जो नेता अपने राज्य में गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाता है, उसे केरल के विकास मॉडल पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने केरल की नीतियों और प्रशासन को लेकर आलोचनात्मक टिप्पणी की थी। इसके जवाब में विजयन ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि यह विडंबना है कि जो व्यक्ति अपने राज्य की मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, वह एक ऐसे राज्य को उपदेश देने की कोशिश कर रहा है, जिसने सामाजिक विकास के कई मानकों पर देश में अग्रणी स्थान हासिल किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रेड्डी उन ताकतों के "मुखपत्र" बन गए हैं, जो केरल के समावेशी और सतत विकास मॉडल को कमजोर करना चाहती हैं।

विजयन ने अपने तर्कों को मजबूत करने के लिए नीति आयोग के आंकड़ों का हवाला दिया और दोनों राज्यों के बीच स्पष्ट तुलना पेश की। उन्होंने कहा कि सतत विकास सूचकांक 2023-24 में केरल 79 अंकों के साथ देश में पहले स्थान पर है, जबकि तेलंगाना छठे स्थान

पर है। उनके अनुसार, यह आंकड़े खुद यह साबित करते हैं कि केरल का मॉडल न केवल प्रभावी है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक उदाहरण भी है।

भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए विजयन ने कहा कि केरल को भारत का सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना जाता है, और ऐसे में इस तरह के आरोप केवल राजनीतिक लाभ के लिए लगाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अपने राज्य की कमियों को छिपाने के लिए केरल का मजाक उड़ाना बेहद निंदनीय है और इससे राजनीति का स्तर गिरता है।

गरीबी के मुद्दे पर भी विजयन ने विस्तार से बात करते हुए कहा कि केरल अत्यधिक गरीबी को लगभग समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। उनके मुताबिक, राज्य की गरीबी दर महज 0.55 प्रतिशत है, जो देश में सबसे कम है, जबकि तेलंगाना में यह दर 5.88 प्रतिशत के आसपास है। उन्होंने दावा किया कि 2025 के अंत तक केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है, जहां अत्यधिक गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

साक्षरता दर को लेकर भी उन्होंने दोनों राज्यों के बीच अंतर को रेखांकित किया। विजयन ने बताया कि केरल की साक्षरता दर 95.3 प्रतिशत है, जो देश में सबसे अधिक है, जबकि तेलंगाना अभी भी 76.9 प्रतिशत पर है। उनके अनुसार, यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि नीतियों और प्राथमिकताओं का भी प्रतिबिंब है।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी विजयन ने केरल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि राज्य की शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) घटकर 5 तक पहुंच गई है, जो विकसित देशों के स्तर के बराबर या उससे बेहतर है। उन्होंने दावा किया कि केरल की मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के कारण यहां के लोग औसत भारतीय नागरिक की तुलना में 5 से 7 वर्ष अधिक जीवन जीते हैं। इसके विपरीत, तेलंगाना में शिशु मृत्यु दर लगभग चार गुना अधिक होने का दावा करते हुए उन्होंने वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाए।

विजयन ने तेलंगाना सरकार द्वारा केरल में राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यदि यही संसाधन अपने राज्य में गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार पर लगाए जाएं, तो वहां की स्थिति कहीं बेहतर हो सकती है। उनके इस बयान ने राजनीतिक बहस को और गर्म कर दिया है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर प्राथमिकताओं और शासन के मॉडल पर सवाल उठाए गए हैं।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब राज्यों के बीच विकास मॉडल को लेकर सीधी राजनीतिक तुलना और टकराव बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर केरल अपने सामाजिक विकास सूचकांकों को लेकर आत्मविश्वास से भरा है, वहीं दूसरी ओर तेलंगाना जैसे राज्य अपनी नीतियों के आधार पर अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

फिलहाल यह बयानबाजी केवल शब्दों तक सीमित है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने गहरे हैं। यह न केवल दो मुख्यमंत्रियों के बीच टकराव है, बल्कि दो अलग-अलग विकास मॉडलों और राजनीतिक दृष्टिकोणों की सीधी भिड़ंत भी है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बहस किस दिशा में जाती है और क्या यह राष्ट्रीय राजनीति के बड़े विमर्श का हिस्सा बनती है।

पटना की सड़कों पर उफनता आक्रोश: TOD योजना और LPG संकट के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन

बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को सियासी तापमान अचानक उस वक्त उबाल पर पहुंच गया, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने राज्य सरकार की बिजली नीति और रसोई गैस की कथित कमी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आयकर गोलंबर पर जुटे सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने न केवल नारेबाजी की, बल्कि नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर अपने गुस्से का इजहार भी किया। इस प्रदर्शन ने साफ संकेत दे दिया कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बिजली दरें और महंगाई बड़े मुद्दे बनने वाले हैं।

दरअसल, इस पूरे विवाद की जड़ में बिहार में लागू की गई 'टाइम ऑफ डे' (TOD) शुल्क प्रणाली है, जिसे बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने हाल ही में मंजूरी दी है। इस नई व्यवस्था के तहत दिन को तीन हिस्सों में बांट दिया गया है—सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफ-पीक समय, शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक पीक समय और रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक सामान्य लोड समय। इस व्यवस्था में सबसे अधिक दरें पीक समय के दौरान लागू होंगी, जब आमतौर पर घरों में बिजली की खपत सबसे ज्यादा होती है।

कांग्रेस का आरोप है कि यह योजना सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर बोझ डालने वाली है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने चुनाव के दौरान 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अब उसी जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उनका कहना था कि टीओडी योजना के तहत शाम 5 बजे के बाद बिजली दरों में 10 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा रही है, जो मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए भारी पड़ने वाली है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस नीति

का असर राज्य के करीब 2.21 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिनमें 1.88 करोड़ घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं। ऐसे में यह केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि एक व्यापक आर्थिक प्रभाव डालने वाला फैसला है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि सरकार इस योजना के जरिए राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि इसका सीधा असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा।

प्रदर्शन के दौरान एलपीजी सिलेंडरों की कथित कमी का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जब राज्य में रसोई गैस की उपलब्धता पहले से ही प्रभावित है, तब सरकार ने बिजली दरों में वृद्धि करके जनता की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। खासतौर पर शाम के समय, जब ज्यादातर घरों में खाना बनाया जाता है, उस समय बिजली महंगी होना आम लोगों के लिए दोहरी मार जैसा है।

राजेश राम ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह नीति जनता के साथ अन्याय है। उनके अनुसार, एक तरफ सरकार मुफ्त बिजली देने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ अलग-अलग शुल्क लगाकर उससे कई गुना अधिक पैसा वसूलने की तैयारी कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जनता से वोट लेने के बाद अब "बदले की भावना" से काम कर रही है।

कांग्रेस ने इस मुद्दे को केवल आर्थिक संकट तक सीमित नहीं रखा, बल्कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाए। नालंदा में हुई भगदड़ की घटना, एक लड़की के साथ कथित मारपीट और जहरीली शराब से हुई मौतों का जिक्र करते हुए पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार इन गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नई-नई नीतियां लागू कर रही है। विपक्ष का कहना है कि बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब हो रही है, लेकिन सरकार इन समस्याओं के समाधान के बजाय राजनीतिक समीकरणों में उलझी हुई है।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की कि टीओडी योजना को तुरंत वापस लिया जाए तथा एलपीजी की आपूर्ति को सामान्य किया जाए। उनका कहना था कि यदि सरकार ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा।

इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जहां सरकार इसे एक आधुनिक और संतुलित बिजली प्रबंधन प्रणाली के रूप में पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इसे आम जनता के खिलाफ उठाया गया कदम बता रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह मुद्दा चुनावी राजनीति का केंद्र बनता है या फिर सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है।

लखनऊ से अखिलेश का सियासी प्रहार: 'हर आवाज दबाई जा रही', 2027 के लिए एकजुटता का आह्वान

उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर तल्ख बयानबाजी का दौर तेज हो गया है, जहां राजधानी लखनऊ से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए सरकार की कार्यशैली, नीतियों और प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। उनके इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और आने वाले चुनावी समीकरणों को लेकर बहस को और तेज कर दिया है।

अखिलेश यादव ने कहा कि आज स्थिति यह हो गई है कि जो भी व्यक्ति सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, उसे किसी न किसी तरीके से चुप कराने की कोशिश की जाती है। उनके अनुसार, यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे आम जनता के अधिकारों पर सीधा असर पड़ता है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सभी लोग एकजुट होकर इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके।

महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि इस क्षेत्र में कोई ठोस काम नहीं हुआ है। उनके मुताबिक, महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर केवल घोषणाएं की गईं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिखता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान वास्तविक विकास के बजाय केवल छवि निर्माण पर ज्यादा केंद्रित है।

शिक्षा और रोजगार जैसे अहम मुद्दों को उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि

प्रदेश में इन दोनों क्षेत्रों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में माध्यमिक विद्यालयों की हालत खराब हो गई है और कई शिक्षण संस्थान बंद होने की कगार पर हैं। अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 'अभिनव विद्यालय' और 'संस्कृति विद्यालय' जैसी पहलें शुरू की थीं, जिनका उद्देश्य शिक्षा के स्तर को सुधारना और छात्रों को बेहतर अवसर देना था। इसके अलावा लैपटॉप वितरण योजना को भी उन्होंने युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि निवेश के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। उनके अनुसार, सरकार की नीतियों में स्पष्टता का अभाव है और यही कारण है कि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण सरकार की नीतियां हैं, जो आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही हैं।

संविधान और शासन व्यवस्था को लेकर भी अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार संविधान के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी मनमर्जी से काम कर रही है। उनके मुताबिक, यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और इससे संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस दिशा में सुधार नहीं हुआ, तो इसका दूरगामी असर देश और प्रदेश दोनों पर पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लेकर भी उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया। 'ग्रीन कॉरिडोर' परियोजना की आलोचना करते हुए उन्होंने इसे 'बर्बादी का कॉरिडोर' बताया और कहा कि इससे जनता को सुविधा के बजाय असुविधा ज्यादा हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों शहर के कई चौराहों पर लोगों को बार-बार रुकना पड़ता है और पुलिस को हर जगह बैरिकेडिंग करनी पड़ रही है।

उन्होंने यहां तक कहा कि यह योजना सही तरीके से तैयार नहीं की गई, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

गोमती रिवरफ्रंट का जिक्र करते हुए भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इसका मूल उद्देश्य नदी की सफाई और सौंदर्यीकरण था, लेकिन वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि यदि यहां क्रूज सेवा शुरू भी कर दी जाए, तो भी नदी की स्थिति में सुधार के बिना इसका कोई खास लाभ नहीं होगा।

अपने पूरे संबोधन में अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर स्पष्ट संकेत दिए और कहा कि समाजवादी पार्टी का लक्ष्य शोषित, पीड़ित और वंचित वर्गों को एकजुट कर सत्ता में वापसी करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की कि वे जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन तैयार करें और जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों को उजागर करें।

यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल अब आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियों को धार दे रहे हैं। अखिलेश यादव के इस आक्रामक रुख से यह साफ है कि विपक्ष आने वाले समय में सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। वहीं अब नजर इस बात पर रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों का किस तरह जवाब देती है और क्या यह सियासी टकराव आगे और तेज होता है।

'मेरे दो मिनट' से सियासी जवाब: राघव चड्ढा का वीडियो बना चर्चा का केंद्र, आलोचनाओं के बीच खुद को बताया मध्यम वर्ग की आवाज

दिल्ली की राजनीति से लेकर संसद तक इन दिनों राघव चड्ढा का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अपनी ही पार्टी आम आदमी पार्टी के भीतर उठी नाराज़गी और आलोचनाओं के बीच चड्ढा ने एक अलग ही अंदाज़ में जवाब देने की कोशिश की है। उन्होंने 'मेरे दो मिनट' शीर्षक से एक वीडियो जारी किया, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बहस, समर्थन और व्यंग्य—तीनों को एक साथ जन्म दे दिया।

करीब 2 मिनट 40 सेकंड का यह वीडियो केवल एक सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह रही कि वीडियो पोस्ट करते समय उन्होंने कोई शब्द नहीं लिखे, सिर्फ भारतीय ध्वज का इमोजी साझा किया। यह एक प्रतीकात्मक संदेश था—जैसे वह खुद को सीधे देश और जनता के मुद्दों से जोड़कर पेश करना चाहते हों, बिना किसी अतिरिक्त बयानबाजी के।

वीडियो की शुरुआत में चड्ढा को संसद भवन में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है, जिसे सिनेमाई अंदाज़ में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अलग-अलग मुद्दों पर उनके भाषणों के अंश जोड़े गए, जो यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे केवल 'छोटे मुद्दों' तक सीमित नहीं हैं, बल्कि व्यापक राष्ट्रीय चिंताओं को भी उठाते रहे हैं। यह वीडियो उस आलोचना का जवाब माना जा रहा है, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि वे तुच्छ मुद्दों—जैसे समोसे की कीमत—को प्राथमिकता देते हैं।

वीडियो में सबसे चर्चित हिस्सा वह था, जहां चड्ढा संसद में कहते नजर आते हैं कि भारत में लोग इंग्लैंड जैसी कर व्यवस्था के तहत टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें सोमालिया जैसी सेवाएं मिलती हैं।

यह बयान पहले भी काफी विवादों में रहा था और अब इसे फिर से सामने लाकर उन्होंने अपनी बात को और तेज़ी से रखने की कोशिश की है।

इसके अलावा, उन्होंने 'राइट टू रिकॉल' जैसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मुद्दे को भी वीडियो में प्रमुखता दी। यह दिखाने का प्रयास था कि उनकी राजनीति केवल आलोचना तक सीमित नहीं, बल्कि सुधार की मांग भी करती है। साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई, आय और खर्च के असंतुलन, विमानन क्षेत्र में बढ़ते द्विाधिकारीकरण और कर प्रणाली में बदलाव की जरूरत जैसे विषयों को भी उठाया।

इस वीडियो की एक खास बात यह भी रही कि इसमें उन्होंने पंजाब से जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भगवंत मान ने उसी दिन उन पर आरोप लगाया था कि वे राज्य के अहम मुद्दों को संसद में नहीं उठा रहे हैं। चड्ढा ने अपने वीडियो में बठिंडा से बीकानेर तक चलने वाली 'कैंसर ट्रेन' का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य संकट की ओर ध्यान खींचा, साथ ही पंजाब में पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता से जुड़े गंभीर सवाल भी उठाए।

इतना ही नहीं, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को भारत रत्न देने की मांग का अपना पुराना बयान भी वीडियो में जोड़ा। यह कदम स्पष्ट रूप से भावनात्मक और वैचारिक दोनों स्तर पर जनता से जुड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं। एक ओर जहां कुछ यूजर्स ने इसे एक मजबूत और प्रभावशाली जवाब बताया, वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने इसे 'इमेज सुधारने की कोशिश' कहकर मजाक भी उड़ाया। मीम्स की बाढ़ आ गई, जिसमें कुछ ने उनके मुद्दों की गंभीरता पर सवाल उठाए, तो कुछ ने उन्हें 'मिडिल क्लास का हीरो' बताते हुए समर्थन दिया।

यह पूरा घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब पार्टी के भीतर ही उनके रोल और प्राथमिकताओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राज्यसभा में AAP के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद यह उनका तीसरा सार्वजनिक प्रतिक्रिया वाला कदम था, जिससे साफ है कि वे अपनी राजनीतिक छवि को लेकर सतर्क हैं और उसे लेकर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह वीडियो केवल एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक 'नैरेटिव बिल्डिंग' का प्रयास है—जहां चड्ढा यह दिखाना चाहते हैं कि वे एक गंभीर, मुद्दों पर आधारित और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। हालांकि, यह रणनीति कितनी सफल होती है, यह आने वाले समय में जनता और पार्टी के भीतर की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।

फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 'मेरे दो मिनट' ने राघव चड्ढा को फिर से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला खड़ा किया है, जहां हर कोई उनके अगले कदम और पार्टी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है।